अपनी सत्रह बरस की यात्रा में झारखंड ने विकास के कुछ मानदंडों को हासिल किया है, तो कुछ मामलों में प्रगति निराशाजनक रही है. राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आंकड़ों और विश्लेषणों के जरिये राज्य की मौजूदा स्थिति और भविष्य की संभावनाओं के आकलन के साथ प्रस्तुत है यह विशेष पेज...

259 एलोपेथिक हॉस्पीटल हैं राज्य के शहरी क्षेत्रों में, जिनमें से 78 क्लास-1 शहरों में, जबकि 31 क्लास-2 शहरों में हैं.

1.52 हैं झारखंड के शहरी इलाकों में औसतन प्रत्येक 1,000 शहरी आबादी के मुकाबले.

0.39 डॉक्टर्स हैं प्रत्येक 1,000 की शहरी आबादी पर राज्य में.

हेल्थ सेंटर्स	कुल संख्या
जिला अस्पताल	24
सब-डिवीजनल अस्पताल	12
सीएचसी	188
पीएचसी	327
सब-सेंटर	3,953

(मार्च, 2016 के मुताबिक)

राज्य में खुलीं विकास की नयी राहें, लेकिन बरकरार हैं चुनौतियां

अलख नारायण शर्मा
अर्थशास्त्री

झारखंड ने 17 साल में कोई सात-आठ प्रतिशत की दर से ग्रोथ किया है. इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के लिए झारखंड को अपने आर्थिक विकास को तेज करना होगा. भारत की औसत प्रति व्यक्ति आमदनी तक पहुंचने के लिए इसे कम-से-कम 11 प्रतिशत की दर से ग्रोथ करना होगा.

झारखंड को एक राज्य के रूप में स्थापित होने के आज 17 साल बाद भी कई ऐसी चुनौतियां हैं, जिनसे पार पाने की जरूरत है. हालांकि, झारखंड ने इन सालों में प्रगति भी की है, लेकिन वह प्रगति काफी नहीं है. आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर के अलावा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के स्तर पर अब भी बहुत कुछ किये जाने की जरूरत है. झारखंड की प्रति व्यक्ति आमदनी राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आमदनी से 50 प्रतिशत कम है. जबकि, झारखंड ने बीते 17 साल में कोई सात-आठ प्रतिशत की दर से ग्रोथ किया है. इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के लिए झारखंड को अपने आर्थिक विकास को तेज करना होगा. भारत की औसत प्रति व्यक्ति आमदनी तक पहुंचने के लिए झारखंड को कम-से-कम 11 प्रतिशत की दर से ग्रोथ करना होगा, तभी वह भारत के औसत प्रति व्यक्ति आमदनी के बराबर पहुंचेगा. यह बड़ी चुनौती है.

झारखंड की दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि यही पर्याप्त नहीं है कि झारखंड का ग्रोथ रेट ही बढ़े. इस राज्य की गरीबी छत्तीसगढ़ के बाद सबसे ज्यादा गरीबी है. यहां तक कि जिस बिहार से यह राज्य निकला है, उस बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी झारखंड से 50 प्रतिशत ज्यादा है. इसका अर्थ यह हुआ कि झारखंड में असमानता ज्यादा है. यह चुनौती हमेशा विकास में बाधक होती है और राज्य सरकार को चाहिए कि वह मानव विकास सूचकांक के हर स्तर पर विकास करने की कोशिश करे. चाहे वह बिजली हो, स्वच्छता हो, शिक्षा हो, भूख हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, इन सभी स्तरों पर जब तक सम्यक रूप से नीति बनाकर काम नहीं किया जायेगा, तब तक मुश्किल है कि झारखंड अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे. हालांकि, झारखंड जैसे संसाधन-संपन्न राज्य के लिए यह कोई मुश्किल नहीं है कि वह इन सूचकांकों को ठीक नहीं कर सकता. लेकिन, इसके लिए इच्छाशक्ति तो चाहिए ही.

झारखंड में कृषि क्षेत्र में पचास प्रतिशत लोग काम करते हैं, लेकिन इससे मुश्किल से 14-15 प्रतिशत ही जीडीपी में योगदान मिल पाता है. वहीं खनन से 12 प्रतिशत जीडीपी आता है, जबकि इस क्षेत्र में सिर्फ 2.3 लोग काम करते हैं. मैन्यूफैक्चरिंग की जीडीपी में हिस्सेदारी 14 प्रतिशत है, जबकि यह क्षेत्र 6.5 प्रतिशत रोजगार देता है. इसका अर्थ यह हुआ कि झारखंड के विकास का पैटर्न बहुत विषम है. यह विषमता कई चुनौतियों को जन्म देती है. इसके बारे में सरकार को गहराई से सोचना पड़ेगा.

दरअसल, टाटा को छोड़कर मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में ज्यादातर उद्योग धंधे पब्लिक सेक्टर के हैं, और ये उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर हैं. झारखंड जैसे गरीब और प्रति व्यक्ति कम आमदनी वाले राज्य में छोटे और मझोले उद्योगों का होना बहुत जरूरी है, ताकि वे लोगों की आर्थिक स्थितियों के हिसाब से वस्तुओं का निर्माण कर सकें. दरअसल, बड़ी औद्योगिक इकाइयों से ज्यादा रोजगार उत्पन्न नहीं होता, उनकी सीमाएं होती हैं और वे शहरों तक ही सीमित रहते हैं. जबकि छोटे और मझोले उद्योगों से ज्यादा रोजगार उत्पन्न होता है. इसलिए मैन्यूफैक्चरिंग और खनन क्षेत्र में जीडीपी तो बहुत आता है, (लगभग 27 प्रतिशत) लेकिन इन दोनों क्षेत्रों से बमुश्किल 10 प्रतिशत ही रोजगार उत्पन्न होता है. इसलिए झारखंड सरकार को चाहिए कि वह छोटे और मझोले उद्योगों की ओर ध्यान दे, ताकि ज्यादा-से-ज्यादा और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी रोजगार की उपलब्धता बन सके.

झारखंड की आधी शहरी आबादी रांची, जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद- इन चार शहरों में रहती है. जो छोटे शहर हैं, वहां कम लोग रहते हैं और उनका ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ाव बहुत कम है. यह स्थिति झारखंड के सर्वांगीण विकास में बाधक है. ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र से जोड़ना बहुत जरूरी है, ताकि विकास बराबर हो सके. हार्टीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, खनन, कृषि, मैन्यूफैक्चरिंग आदि क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को लगाने के बहुत जरूरी है. हाल के सालों में झारखंड में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है. सरकार सुदूर गांवों का विकास कर और तमाम पर्यटन की जगहों को सड़कों से जोड़कर राज्य के विकास को बढ़ा सकती है.

झारखंड में शिक्षित महिलाओं में पचास प्रतिशत में बेरोजगारी है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह संख्या 18 प्रतिशत है. वहीं राज्य के युवाओं में भी पचास प्रतिशत बेरोजगारी है. यही तो बड़ी समस्या है, जो आर्थिक विकास को रोके हुए है.

शिक्षा की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है और यह रोजगार बढ़ाने में बड़ी बाधक है. मेरे ख्याल में राज्य सरकार को इसके लिए एक 'हायर एजुकेशन मिशन' का व्रत लेना चाहिए और 2025 तक सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन को अनिवार्य कर देना चाहिए, और 25 प्रतिशत इनरोलमेंट ग्रोथ के लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए. क्योंकि, भारत के औसत स्किल (कौशल) के मुकाबले झारखंड में स्किल बहुत कम है. इसके लिए जरूरी है कि एजुकेशन सिस्टम बहुत सुदृढ़ हो, तभी बच्चों में कौशल का विकास हो पायेगा और रोजगार बढ़ने के साथ-साथ राज्य में प्रति व्यक्ति आमदनी भी बढ़ेगी. स्वास्थ्य का हाल भी ऐसा ही है. झारखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बहुत कमजोर है. शिक्षा और स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए साल 2025 का लक्ष्य अगर अब से भी निर्धारित कर लिया गया, तो उम्मीद है कि यह राज्य तेजी से विकसित होगा.

राज्य में नक्सली हिंसा एक बहुत बड़ी समस्या रही है. हालांकि, हाल के दिनों में इसमें कुछ कमी जरूर आयी है. लेकिन, अब भी इस समस्या की अनदेखी नहीं की जा सकती. गरीबी और बेरोजगारी ही इस समस्या के मूल में हैं. इसलिए इनमें सुधार करके ही नक्सली समस्या को खत्म किया जा सकता है. मेरी समझ से जब झारखंड का सम्यक विकास होगा, तभी नक्सली समस्या दूर होगी, क्योंकि तब नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी विकास की मुख्यधारा में शामिल होंगे और सुकून की जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे.

शिक्षा की स्थिति

राज्य में कुल सरकारी स्कूलों की संख्या 40,437 है, जिनमें 25,791 प्राथमिक स्कूल, 12,674 प्राथमिक के साथ उच्च प्राथमिक स्कूल, 42 प्राथमिक के साथ उच्च प्राथमिक, सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी स्कूल, 58 उच्च प्राथमिक, 369 उच्च प्राथमिक के साथ सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी स्कूल, 1,373 प्राथमिक के साथ उच्च प्राथमिक व सेकेंडरी स्कूल और 130 उच्च प्राथमिक के साथ सेकेंडरी स्कूल हैं. 2,587 निजी स्कूल और 4,418 मदरसा हैं राज्य में.

स्रोत : स्टेट रिपोर्ट कार्ड, डीआइएसइ 2015-16

सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या

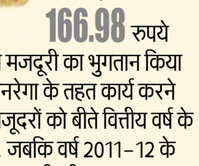

राज्य में सेकेंडरी स्कूल में नियमित शिक्षकों की संख्या 14,702 है, जबकि अनुबंध आधारित शिक्षकों की संख्या 1,892 है.
हायर सेकेंडरी स्कूल में नियमित शिक्षकों की संख्या 6,446 और अनुबंध आधारित शिक्षकों की संख्या 708 है.

स्रोत : सेकेंडरी एजुकेशन, फ्लैश स्टेटिस्टिक्स, डीआइएसइ 2015-16

ग्रामीण रोजगार

ग्रामीण विकास विभाग के तहत झारखंड स्टेट लाइवलिहुड प्रोमोशन सोसाइटी के तौर पर स्वायत्त सोसाइटी का गठन किया गया, जिसके जरिये राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार पैदा करने के लिए अवसर मुहैया कराने पर जोर दिया जा रहा है.

42 नये प्रखंड शामिल किये गये हैं झारखंड स्टेट लाइवलिहुड प्रोमोशन सोसाइटी के दायरे में साल 2016-17 के दौरान.

66,300 लाख रुपये आबंटित किये गये हैं साल 2016-17 के दौरान दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत, जिसे तीन साल की अवधि के लिए जारी किया गया है.

12,582 युवाओं को ट्रेनिंग मुहैया करायी जा चुकी है दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत, जिनमें से 3,374 युवाओं को रोजगार हासिल हो चुका है.

14,489 युवा जुड़े हुए हैं इस कौशल योजना से राज्यभर में मौजूदा समय में.

512 लाख मैनडेज यानी प्रति व्यक्ति कार्य दिवस के हिसाब से रोजगार पैदा हुआ बीते वित्तीय वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्यभर में.

20.13 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया मनरेगा के तहत बीते वित्तीय वर्ष के दौरान.

166.98 रुपये औसत मजदूरी का भुगतान किया गया मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूरों को बीते वित्तीय वर्ष के दौरान, जबकि वर्ष 2011-12 के दौरान मजदूरी की यह दर 121.85 रुपये थी.

ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर

516 किलोमीटर घनत्व है झारखंड में ग्रामीण सड़कों का प्रत्येक 1,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 806.6 है. इस गैप को पाटने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने विविध योजनाएं तैयार की हैं.

8,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर रहा है ग्रामीण विकास विभाग, जिनका निर्माण मौजूदा वित्तीय वर्ष के आखिर तक पूरा होने की उम्मीद है.

16,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण की योजना है ग्रामीण विकास विभाग की आगामी सालों के लिए.

716 किलोमीटर औसत घनत्व हो जायेगा झारखंड में सड़कों का प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में, उपरोक्त सड़कों का निर्माण पूरा होने के बाद आने वाले सालों के दौरान.

1,635 करोड़ रुपये आबंटित किये गये साल 2015-16 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत राज्यभर में, जिसके तहत 2,871 किमी 889 सड़कों का निर्माण किया गया.

284 पुलों का निर्माण शुरू किया गया साल 2015-16 के दौरान मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत राज्यभर में.

खाद्य सुरक्षा

80 फीसदी आबादी झारखंड में खाद्य सुरक्षा के दायरे में आती है.

60.2 फीसदी शहरी आबादी है खाद्य सुरक्षा के तहत.

86.4 फीसदी ग्रामीण जनसंख्या को लाया जा चुका है खाद्य सुरक्षा स्कीम के तहत राज्यभर में.

474 गोदाम हैं राज्य में और 158 निर्माणाधीन हैं.

2,40,750 टन कुल भंडारण क्षमता है इन गोदाम की.

(स्रोत : झारखंड इकोनोमिक सर्वे 2016-17)

- चौथे नंबर पर है झारखंड देश के अन्य राज्यों के मुकाबले विकास दर के मामले में.
- गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा, महज इन तीन राज्यों की विकास दर ही है झारखंड से अधिक.
- झारखंड की प्रति व्यक्ति आय देश के औसत से काफी कम है.
- **2,41,955** रुपये रही झारखंड की जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्ष 2015-16 के दौरान.
- **8.8** फीसदी औसत की दर से वृद्धि हुई झारखंड राज्य की जीएसडीपी में वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान, जो भारत की जीडीपी के औसत वार्षिक दर (6.8 फीसदी) से कहीं ज्यादा रही.
- **12** फीसदी की दर से औसतन बढ़ोतरी हुई है झारखंड में विकास दर में पिछले दो वर्षों के दौरान, जबकि देशभर में यह आंकड़ा महज सात फीसदी के आसपास ही रहा है.

(स्रोत : झारखंड इकोनोमिक सर्वे 2016-17)

विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा झारखंड

बन रही है राज्य की सकारात्मक छवि

डॉ शिव शक्ति बक्सी
टिप्पणीकार

किसी भी प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए एक सकारात्मक 'ब्रांडिंग' की जरूरत है, जो विकास की एक दीर्घकालिक संपूर्ण योजना, नेतृत्व की कड़ी मेहनत व दूरदर्शिता से ही संभव है.

पिछले वर्ष संपन्न 'मोमेंटम झारखंड इन्वेस्टर्स समिट' से झारखंड का नाम देश-विदेश में चर्चा में रहा है. दिल्ली में रहने वाले झारखंड के लोगों से अभी हाल ही में प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों के मिलने का कार्यक्रम संपन्न हुआ. कहीं-न-कहीं झारखंड इतने वर्षों से बनी अपनी छवि से बाहर निकलना चाह रहा है. प्रदेश की सीमाओं से निकल राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंचों पर झारखंड अपनी नयी पहचान स्थापित करने को आतुर दिखता है. देश के विकास के मानचित्र पर अब गुजरात के बाद झारखंड दूसरा सबसे तेज विकास दर वाला प्रदेश बन चुका है. श्रम-सुधारों के मामले में तो यह देश में अव्वल है और 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' में देश के प्रथम सात राज्यों में इसे गिना जा रहा है. वर्षों बाद झारखंड कुछ सकारात्मक उपलब्धियों के लिए जाना जा रहा है.

दशकों के संघर्ष के बाद जब झारखंड बना, तब शायद ही किसी को इसके देश के अग्रणी प्रदेशों में गिने जाने पर संदेह हुआ होगा, परंतु झारखंड पिछड़ता और राज्य में निराशा का माहौल बना. प्रचुर खनिज एवं वन संपदा, मेहनतकश किसान-मजदूर, मेधावी युवा और विकास की ओर कदम बढ़ाने को तत्पर आम-जन के बाद भी विकास के मानदंडों पर झारखंड उत्साहजनक नतीजे हासिल करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था. अस्थिर राजनैतिक माहौल, बनती-बिगड़ती सरकारें, आयाराम-गयाराम का खुला खेल, भ्रष्टाचार और नक्सल-माओवादी आतंक की खबरों ने झारखंड के भविष्य पर कई प्रश्नचिह्न खड़े कर दिये. अकूत संसाधनों की उपलब्धता के बाद भी राजनैतिक अस्थिरता के कारण प्रदेश का नेतृत्व कड़े फैसलों के जरिये चुस्त-दुरूस्त प्रशासन नहीं दे पा रहा था. प्रदेश की राजनीति भ्रष्टाचार व सत्ता के बंदरबांट का माध्यम बनने लगी और राजनैतिक इच्छाशक्ति तथा दूरदृष्टि की भारी कमी दिखाई दे रही थी. विधानसभा चुनावों में बार-बार खंडित जनादेश से राजनैतिक नेतृत्व के हाथ बंधे रहते थे और प्रदेश के संसाधनों का दोहन हो रहा था. संसाधनों से धनी प्रदेश की जनता मजबूरी व मायूसी से झारखंड की पूंजी को लुटते-बिखरते देख रही थी. इन सब का असर यह हुआ कि झारखंड के विकास के लिए कोई दीर्घकालिक 'रोडमैप' तैयार नहीं हो पाया. झारखंड के साथ ही बने अन्य प्रदेश जहां विकास की राह में कई सशक्त कदम उठा रहे थे, वहीं झारखंड पर राजनैतिक अस्थिरता व अनिश्चितता के काले बादल छाये रहे. असीम संभावनाओं से भरा प्रदेश पिछड़ता चला गया.

यह विडंबना ही है कि देश का लगभग 40 प्रतिशत खनिज जिस प्रदेश से प्राप्त होता हो, वहां की करीब 40 फीसदी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन-बसर करने पर मजबूर हो. प्रति व्यक्ति आय, शहरीकरण व स्वास्थ्य विकास के पैमानों पर प्रमुख मानदंड माने जाते हैं. प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों में झारखंड देश में सबसे गरीब पांच प्रदेशों में गिना जाता है. देश में शहरीकरण का प्रतिशत 31.16 है, जबकि झारखंड में यह अब भी केवल 24.1 प्रतिशत है. राज्य के करीब 20 फीसदी बच्चे कुपोषित हैं. अधिकतर नीतियां खनिज संपदाओं का दोहन तथा प्रदेश की जनता को इनसे प्राप्त राजस्व व इन पर आधारित अन्य उद्योगों पर आधारित हैं. नतीतन कृषि की व्यापक उपेक्षा हुई और किसानों को सिंचाई के उपयुक्त साधन नहीं मुहैया कराये गये हैं. यदि वैज्ञानिक तरीके से खेती को बढ़ाया गया होता, तो गांवों-जंगलों में बसने वाले लोग कोयला ढोने और वन-उपज बीनने को मजबूर नहीं होते. इन सब आंकड़ों में निरंतर सुधार तो हो रहा है, परंतु हमें यह याद रखना होगा कि झारखंड स्वतंत्रता के बाद से ही निरंतर उपेक्षा का शिकार होता रहा तथा इस क्षेत्र की नीतियां यहां के स्थानीय लोगों को ध्यान में रखकर कम ही बनायी गयी.

पूरे देश में विकास का माहौल बना है. प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 'टीम इंडिया' को विकास की स्वस्थ स्पर्धा में शामिल होने के आह्वान से सभी प्रदेश विकास के विभिन्न मानदंडों पर अपनी छाप छोड़ने के लिए प्रयासरत हैं. झारखंड की जनता ने इस बार खंडित जनादेश नहीं दिया और उसके सुपरिणाम भी दिखने लगे हैं. बिहार से अलग होने के बाद झारखंड को स्वयं को एक उभरते हुए प्रदेश के रूप में स्थापित करना था तथा देश-विदेश में 'झारखंड-वासी' के रूप में एक सशक्त पहचान बनानी थी, परंतु दुर्भाग्य से राजनैतिक अस्थिरता व घोटालों आदि से प्रदेश की उत्साहजनक छवि नहीं बन पायी. किसी भी प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए एक सकारात्मक 'ब्रांडिंग' की जरूरत है, जो विकास की एक दीर्घकालिक संपूर्ण योजना, नेतृत्व की कड़ी मेहनत व दूरदर्शिता से ही संभव है. लंबे समय तक निरंतर कठिन परिश्रम से ही सकारात्मक छवि निर्माण संभव है, जिसका लाभ आने वाले समय में पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्राप्त होता है. इसी के आधार पर ही झारखंड भी अपनी अस्मिता एवं पहचान को परिभाषित एवं सुदृढ़ कर सकता है. वर्तमान सरकार की उपलब्धियों से झारखंड की धमक अब देशभर में सुनाई पड़ने लगी है, लेकिन प्रदेश को अभी संकल्पबद्ध होकर एक लंबे दौर से गुजरना पड़ेगा तथा विकास की एक नयी इबारत लिखनी पड़ेगी.

औद्योगिक सेक्टर में वृद्धि

7.2 फीसदी की औसत वार्षिक दर से औद्योगिक सेक्टर में वृद्धि हुई झारखंड में साल 2011-12 से 2015-16 के दौरान.

83 हजार करोड़ रही इस सेक्टर में हुए आउटपुट की वैल्यू स्थिर मूल्यों पर साल 2011-12 से 2015-16 के दौरान.

8.5 फीसदी औसतन सालाना की दर वृद्धि हुई मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर (जो औद्योगिक सेक्टर में शामिल है और इसकी हिस्सेदारी करीब 50 फीसदी तक है) में साल 2011-12 से 2015-16 के दौरान.

7.2 फीसदी की सालाना औसतन रूप से बढ़ोतरी हुई माइनिंग व क्वारीइंग यानी खनन सेक्टर में साल 2011-12 से 2015-16 के दौरान.

8 फीसदी सालाना औसतन दर से बढ़ोतरी हुई बिजली, गैस और जलापूर्ति क्षेत्र में साल 2011-12 से 2015-16 के दौरान.